xjhch js[kk ds uhps thou&;kiu dj jgs ifjokjksa dk ,d vkfFkZd ,वं सामाजिक अध्ययन : झारखण्ड प्रदेशk ds prjk ftyk ds V.Mok iz[k.M के विशेषk lanHkZ esa

Lkekt foKku ladk; ds अर्थशkkL= fo"k; esa ih,p-Mh- dh mikf/k ds fy, iLrqr 'kks/k iLrko

jkaph fo'ofo|ky;] jkaph

2024

'kks/k funsZ'kd

Mk- ज्योति प्रकाशk

Lkgk;d izk/;kid]

अर्थशkkL= foHkkx]

jkaph fo'ofo|ky;] jkaph

>kj[k.M

'kks/kkFkhZ

जय प्रकाशk jtd

xjhch js[kk ds uhps thou&;kiu dj jgs ifjokjksa dk ,d vkfFkZd ,oa lkekftd v/;;u % >kj[k.M izns'k ds prjk ftyk ds V.Mok iz[k.M ds fo'ks"k lanHkZ esa

ifjp; %

साधारणतः जब किसी व्यक्ति के पास इतनी भी आय या भौतिक सम्पत्ति न हो कि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो उसे गरीब कहते हैं। गरीबी सिर्फ आर्थिक न होकर सामाजिक एवं राजनीतिक तत्वों का मिश्रण भी हो सकता है। भोजन, वस्त्र और आवास जैसे मुलभूत व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों का पूर्ण अभाव ही पूर्ण गरीबी है।

गरीबी की अनेक परिभाषाएं हैं पर विद्वानों में इस बात पर सहमती नहीं है कि भारत के संदर्भ में कौन सी परिभाषा उपयुक्त है। भारत के अंदर आय आधारित गरीबी परिभाषा और उपभोग आधारित गरीबी परिभाषा दोनों उपयोग में है।

भारत के बाहर, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएँ क्रय शक्ति समानता (PPP) के साथ–साथ नाम मात्र सापेक्ष आधार पर भारत सहित अन्य देशों के बीच गरीबी की तुलना करने के लिए एक व्यापक परिभाषा का उपयोग करती है।

भारत के चिन्भिक राज्यों में में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं की क्या स्थिति है, इसे जानने के लिए राज्यो की अपनी–अपनी परिभाषाएँ है। परिभाषाओं में ये अंतर आंतरिक रूप से और दुनिया के अन्य विकासशील देशों के तुलना में भारत में गरीबी के बारे में एक विरोधाभासी तथा जटिल तस्वीर प्रस्तुत करती है।

गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसके कम होने पर व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। भारत में आज भी एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहा है।

हाल ही में सांसद नुसरत जहां ने योजना मंत्रालय से भारत में गरीबी से जुड़े आंकड़ों का एक डेटा मांगा था जिसपर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कॉरपोरेट कार्य मंत्री के दिये गये जवाब के अनुसार देश में

पिछले दशक में गरीबी का कोई आकलन नहीं हुआ है। पिछला आकलन वर्ष 2011–12 में हुआ था जिसके अनुसार देश में भारत में 27 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहते है। आज भी करीब 21.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने के लिए मजबूर हैं। अर्थात् 2697.38 लाख गरीब हैं जिनके आँकड़े सरकार के पास है जिनमें से करीब 21 करोड़ गरीब सिर्फ ग्रमीण इलाके में रहते हैं यानि भारत देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यान करने वालों का एक बड़ा हिस्सा गाँवों में निवास करता है।[1]

एन.एस.एस.ओ. के 68वाँ राउण्ड (2011–12)[2] के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 21.9 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है जिसमें ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 25.7 एवं शहरी गरीबी का प्रतिशत 13.7 है। छोटे राज्यों में हाल ज्यादा बुरा है। दादर और नागर हवेली में यह प्रतिशत 39.31 प्रतिशत, झारखण्ड में 39.96 प्रतिशत, ओड़िसा में 32.59 प्रतिशत है। इसी प्रकार बिहार में करीब 33 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 29 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। छोटे राज्यों की स्थिति इस संदर्भ में अत्यधिक खराब है। 2011–12 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों के आँकड़े तालिका संख्या 1 में दर्शाई गई है।

एन.एस.एस.ओ. के 68वाँ राउण्ड (2011–12) के आधार पर 45.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 31.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 22.6 प्रतिशत छिड़े वर्ग के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में इनक प्रतिशत क्रमशः 24.1 प्रतिशत, 21.7 प्रतिशत, 21.7 प्रतिशत हैं। जहाँ तक गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रश्न है सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार शहर में रहने वाला व्यक्ति 32 रूपये और गाँव में रहने वाला व्यक्ति 26 रूपये प्रतिदिन यदि नहीं खर्च कर पा रहा है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जायेगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य है जबकि झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़िसा और असम में भी गरीबी अपने चरम पर है।

सरकार के इस आकलन की बहुत आलोचना हुई। गरीबी रेखा के बारे में मानदंड इस तथ्य को प्रतिबिंबित करते हैं कि गरीबी रेखा के मानक दशकों पहले निर्धारित किये गये थे। उस समय जब भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए मात्र निर्वाह भी सुनिश्चित नहीं था। बेशक, गरीबी रेखा को मूल्य वृद्धि के अनुरूप नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के लिए नहीं।

Rkkfydk & 1 % Hkkjr esa lkr jkT;ksa ds 'kgjh ,oa xzkeh.k {ks=ksa esa xjhch js[kk ls uhps dh tula[;k ¼2011&12½ rsanqydj fof/k ij vk/kkfjr										
jkT;	Xkzkeh.k					'kgjh				
	vuq- tutkfr	vuq- tkfr	fiNMk oxZ	vU;	dqy	vuq- tutkfr	vuq- tkfr	fiNMk oxZ	vU;	dqy
असम	33.4	28.2	34.4	34.9	33.9	15.6	30.5	11.0	21.2	20.6
बिहार	59.3	51.7	31.3	23.3	34.1	10.3	43.0	32.9	17.8	31.2
छत्तीसगढ़	52.6	48.2	38.7	7.7	7.7	35.2	39.5	24.9	10.6	24.8
झारखण्ड	51.6	40.4	36.4	31.3	31.3	28.7	40.6	28.2	12.5	24.8
मध्य प्रदेश	55.3	41.3	24.7	19.6	35.7	32.3	33.2	21.0	13.1	21.0
ओड़िसा	63.5	41.4	24.2	14.2	35.7	39.7	26.3	22.1	6.7	17.3
उत्तर प्रदेश	27.0	41.1	30.7	12.5	30.4	16.3	39.1	32.1	12.8	26.1
Hkkjr	**45.30**	**31.50**	**22.60**	**15.50**	**25.70**	**24.10**	**21.70**	**15.40**	**8.10**	**13.70**

Lok Sabha Unstarred Question No. 924,dated on 02.03.2015 ; https://www.indiastat.com

आज की गरीबी रेखा उस न्यूनतम राशि (शहर में रहने वाला व्यक्ति 32 रूपये और गाँव में रहने वाला व्यक्ति 26 रूपये प्रतिदिन) से बिल्कुल मेल नहीं खाती है जो हर किसी को चहिए।[3] वर्त्तमान महँगाई के दौर में गरीबी रेखा के निर्धारण में उपर्युक्त राशि बहुत कम है। विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम खर्च करने वाले लोग बेहद गरीब माने जायेंगे, जबकि इसके पहले यह पैमाना 1.25 डॉलर प्रतिदिन खर्च का था।[4]वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था और यह गरीबी की घटनाओं और तीव्रता को निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों का उपयोग करता है।

मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) एक व्यापक मापन उपकरण है जिसका उपयोग पैसों या मौद्रिक पहलु के साथ–साथ गरीबी के कई आयामों की अवश्यकताओं को मापने के लिए किया जाता है। यह पारंपरिक आय के आधार पर गरीबी मापन के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है ताकि गरीबी मापन को एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके और नीति निर्धारकों को अवश्यकता के विभिन्न पहलुओं का पता चले।

एमपीआई लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके गरीबी की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। यह नीति निर्माताओं को अभाव के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने और तदनुसार हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने में मदद करता है। विभिन्न देश और संगठन अपने विशिष्ट संदर्भों और डेटा उपलब्धता के अनुरूप एमपीआई को अनुकूलित कर सकते हैं

एन.एस.एस.ओ. के 68वाँ राउण्ड (2011–12)[5] के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 21.9 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है जिसमें ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 25.7 एवं शहरी गरीबी का प्रतिशत 13.7 है जबकि 2004–05 में कुल जनसंख्या का 37.24 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करते थे जहाँ ग्रामीण एवं शहरी गरीबी का प्रतिशत क्रमशः 41.8 एवं 25.7 था। अतः विश्व स्तर पर एंव भारत पर भी गरीबी में जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आई है।

झारखण्ड में गरीबी की स्थिति योजना आयोग के 24 जुलाई 2013 के रिपोर्ट के अनुसार कुल 36. 98 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं जिसमें ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत शहरी गरीबी से अधिक है। ग्रामीण और शहरी गरीबी का प्रतिशत क्रमशः 40.84 प्रतिशत एवं 24.83 प्रतिशत है। यह प्रतिशत मात्र तीन राज्यों (बिहार, छत्तिसगढ़ और दादर एवं नागर हवेली) से कम है। झारखण्ड में जहाँ ग्रामीण गरीबी 21.65 करोड़ है वही शहरी गरीबी 5.28 करोड़ है। ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी के लगभग चार गुणा के बराबर है। वहीं झारखण्ड में जिलावार गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक गरीबी गढ़वा (54 प्रतिशत) एवं सबसे कम गरीबी रामगढ़ (25.33 प्रतिशत) जिला में है। वहीं चतरा जिले में 36.41 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करते हैं और बी.पी.एल. धारी है और राज्य में यह 10वाँ स्थान रखता है।[6]

विश्व बैंक (2014) के अनुमान से ज्ञात होता है कि विश्व जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत हिस्सा भारत का है एवं 20.6 प्रतिशत विश्व के निर्धनतम् लोगों का है। यु.एन.डी.पी. के 2010 के आँकड़ों के अनुसार, 37. 2 प्रतिशत भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करते हैं।[7]

प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण गरीबी 1973–74 में 56.44 प्रतिशत से घटकर 2004 में 27 प्रतिशत हो गई है, किन्तु चिन्ता का विषय यह है कि ग्रामीण गरीबी अभी भी .25.7 प्रतिशत है। गरीबों में लिंग असमानता और भी अधिक चिंता का विषय है।

यदि एन.एन.एस.ओ. के 68वें राउण्ड (2011–12) को देखते है तो पाते हैं कि प्रति व्यक्ति मासिक व्यय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 1430 रू एवं शहरी क्षेत्रों में 2630 रू. है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 84 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों के औसत मासिक व्यय में 53 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं पर व्यय करते हैं वहीं शहरी क्षेत्रों में इसका प्रतिशत 43 प्रतिशत है।

विश्व बैंक की मानें तो गरीबी को मापने के लिए संशोधित पद्धति का उपयोग करते हुए, 2012 में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में गरीब लोग थे, जो इसकी विशाल आबादी को दर्शाता है। हालाँकि, प्रतिशत के मामले में, बड़ी गरीब आबादी वाले अन्य देशों की तुलना में इसका स्कोर कुछ कम है। जुलाई 2018 में, वियना स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक ने बताया कि 44% या 87 मिलियन नाइजीरियाई लोगों की तुलना में कम से कम 5.3% या 70.6 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। 2019 में, कुल जनसंख्या की प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम कमाई के मामले में नाइजीरिया और कांगो ने भारत को पीछे छोड़ दिया। हालांकि भारत को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद है। एक समय में अत्यधिक गरीबी के कारण, इसकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रति दिन 3.2 डॉलर से भी कम पर जीवन–यापन करता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रूप से निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आ जाती है।

भारत अपनी घरेलू गरीबी रेखा का निर्धारण घर के सदस्यों की व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा के योग द्वारा करता है। यह प्रथा कई विकासशील देशों के समान है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशो से भिन्न है जो प्रति अतिरिक्त घरेलू सदस्य के आधार पर अपनी गरीबी रेखा का निर्धारण करते है। वर्ष 2014 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सदस्य वाले परिवार के लिए गरीबी रेखा 11670 डॉलर प्रति वर्ष जबकि चार सदस्यीय परिवार के लिए 23850 डॉलर प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी।

गरीबी की परिभाषा पर विद्वान इस बात पर असहमत हैं कि भारत के लिए कौन सी परिभाषा उपयुक्त है। भारत में आय–आधारित गरीबी परिभाषा और उपभोग–आधारित गरीबी परिभाषा दोनों उपयोग में हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की अपनी गरीबी सीमा है तथा यह निर्धारित करने के लिए कि कितने लोग उसकी गरीबी रेखा से नीचे हैं और क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2011–12 में पाँडेचेरी के ग्रामीण क्षेत्र में 1301 रूपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1309 रू. प्रतिमाह गरीबी रेखा निर्धारित की गई जबकि ओड़िसा के ग्रमीण क्षेत्रों के लिए 695 रू. प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 861 रू. प्रतिमाह निर्धारित की गई।

कई देशों की तरह, भारत में निर्वाह खाद्य मानक का उपयोग करके गरीबी को परिभाषित और अनुमानित किया गया था। इस पद्धति को संशोधित किया गया है. भारत की वर्तमान आधिकारिक गरीबी दर तथाकथित तेंदुलकर पद्धति से प्राप्त योजना आयोग के आंकड़ों पर आधारित है। यह गरीबी को वार्षिक आय के संदर्भ में नहीं, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की एक टोकरी के लिए एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उपभोग या खर्च के संदर्भ में परिभाषित करता है। इसके अलावा, यह पद्धति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग गरीबी रेखाएं निर्धारित करती है । 2007 से, भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी आधिकारिक सीमा रू. 26 प्रति दिन (+0.43) और शहरी क्षेत्रों में लगभग रू 32 प्रति दिन (+0.53) निर्धारित की हालाँकि

ये संख्याएँ विश्व बैंक की 1.25 डॉलर प्रति दिन की आय –आधारित परिभाषा से कम हैं, यह परिभाषा 2008 में चीन की प्रति दिन 0.65 अमेरिकी डॉलर की आधिकारिक गरीबी रेखा के समान है।[8]

विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की परिभाषा क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर डॉलर 1.25 प्रति दिन पर आधारित है। यह परिभाषा इस तथ्य से प्रेरित है कि दुनिया भर में स्थानीय मुद्राओं में परिवर्तित होने पर समान वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में काफी अंतर हो सकता है। गरीबी की यथार्थवादी परिभाषा और तुलना में जीवन–यापन की लागत में इन अंतरों पर विचार किया जाना चाहिए, या क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर होना चाहिए। इस आधार पर, मुद्रा में उतार–चढ़ाव नाममात्र की महत्वपूर्ण रह जाती है, तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को एक टोकरी की स्थानीय लागत पर आधारित की जाती है जिसे लोग खरीद सकते हैं। विश्व बैंक की 2014 की पीपीपी परिभाषा के अनुसार, भारत की गरीबी दर पहले की तुलना में काफी कम है।

'kks/k leL;k

प्रस्तावित शोध झारखण्ड राज्य के चतरा जिले के टण्डवा प्रखण्ड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करना है। झारखण्ड राज्य की स्थापना 15 नवम्बर 2000 को बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से को अलग कर किया गया। झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत 24 जिले हैं जिनमें चतरा जिला एक अतिपिछड़ा और गरीब जिला है जो हाल के वर्षों में नक्सल समस्या से जूझता रहा है जो इसके आर्थिक विकास में एक प्रमुख अवरोधक है।

यदि भारत के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में गरीबी रेखा के निर्धारण को देखा जाय तो झारखण्ड भारत के गरीब राज्यों में से एक है। यद्यपि झारखण्ड में खनिजों की प्रचूर उपलब्धता है परन्तु इसके सकारात्मक दोहन और उपयोगिता के अभाव के कारण राज्य गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। चतरा जिला में कोयले की खदाने हैं जिनमें स्थानीय मजदूर कार्य करते हैं परन्तु नक्सल प्रभाति क्षेत्र होने के कारण खनिज आधारित उद्योग तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायेजित योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी मुशिकिलों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण यहाँ के निवासियों के आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इस जिले की गरीबी का यह एक प्रमुख कारण है।

rkfydk & 2 % p;fur ladsrdksa ds vk/kkj ij Hkkjr ds lkr jkT;ksa dh cgqvk;keh xjhch lwpdkad fLFkfr ¼2005&06½

jkT;	'kS{kf.kd fLFkfr efgyk 15&49 वर्श izfrशkr	6&14 o"kZ ds cPpksa dh Ldwy esa mifLFkfr izfrशkr	fशkशkq eR;q&nj ¼5 o"kZ ls de½ izfr 1000	14 o"kZ rd ds cPps iwjh rjg ls izfrjf{kr izfrशkr	U;wu ch-,e-vkbZ okyh efgyk,a izfrशkr	Xkjhch js[kk ls uhps tula[;k izfrशkr	izfr O;fDr vk; :0@o"kZ
असम	63.0	84.4	85.0	31.4	36.5	34.4	6,000
बिहार	37.0	62.2	84.8	32.8	45.1	54.4	3,530
छत्तीसगढ़	44.9	81.1	90.3	48.7	43.4	49.4	5,306
>kj[k.M	**37.1**	**71.7**	**93.0**	**34.2**	**43.9**	**45.3**	**4,833**
मध्य प्रदेश	44.4	89.1	94.2	40.1	41.7	48.6	4,125
तमिलनाडु	69.4	93.9	32.5	30.9	18.4	39.4	7,000
उत्तर प्रदेश	44.8	77.2	90.4	51.0	26.0	40.9	4,300
भारत	55.1	79.6	74.1	43.5	35.6	37.2	5,999

Lkzksr % uशkuy QSfeyh gsYFk losZ ¼,u-,Q-,p-,l-½ MkVk 2005&06] uशkuy lsEiy losZ ¼,u-,l-,l MkVk½ 2004&05 ,oa bafM;k g;weu MoyiesaV losZ ¼2005&06½ ij vk/kkfjrA[9]

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि सात प्रमुख राज्यों – बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुआयामी गरीबी सूचकांक में काफी लंबे समय से खराब हैं, साथ ही गरीबी का स्तर भी उच्च है। ये आंकड़े बताते हैं कि 8–11 वर्ष की आयु के आधे से भी कम बच्चे बहुत ही साधारण पढ़ाई में उत्तीर्ण हो पाते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 23 प्रतिशत छोटे बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाता है, और बिहार में आधी से अधिक आबादी भारत सरकार की बेहद कम गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

झारखण्ड के संदर्भ में भी यही स्थिति है। उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 205–06 मे झारखण्ड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली जनसंख्या 45.3 प्रतिशत थी तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मात्र 4,833 रू. थी। महिलाओं में साक्षरता मात्र 37.1 प्रतिशत जो भारत में महिला साक्षरता दर (55.1 प्रतिशत) से बहुत कम थी। इसी प्रकार वर्ष 2005–06 में शिशु मृत्युदर 93 प्रति 1000 थी जो देश के आँकड़े (74 प्रति 1000) की तुलना में बहुत अधिक थी। झारखण्ड में 14 वर्ष तक आयुवर्ग के केवल 34.2 प्रतिशत बच्चों का ही टीकाकरण हुआ था और पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित थे तथा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 71.7 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते थे। महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि लगभग 43.9 प्रतिशत महिलओं का बी.एम.आई (बॉडी मास वेट) न्यूनतम मानक से कम पाया गया।

or'eku fLFkfr

जहाँ तक झारखण्ड का प्रश्न है एन.एस.एस.ओ. के 68वाँ राउण्ड (2011–12)[10] सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 39.96 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करते हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के 51.6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 40.4 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के 36.4 प्रतिशत और अन्य 31.3 प्रतिशत है वहीं शहरी क्षेत्रों में इनके प्रतिशत क्रमशः 28.7 प्रतिशत, 40.6 प्रतिशत, 28.2 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत है। इस प्रकार झारखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 40.8 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 24.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं।

Rkkfydk 3 % >kj[k.M d: fofHkUu ftyk: e: xjhch j:[kk l: uhp: thou;kiu dju: okyh **जनसंख्या का प्रतिशत**

ftyk	Xkjhch j:[kk l: uhp: dh **जनसंख्या का प्रतिशत**
चतरा	63.10
पाकुड़	61.73
पश्चिमी संहभुम	64.13
सहिबगंज	55.93
दुमका	52.93
लातेहार	52.71
गोड्डा	51.81
जामताड़ा	50.56
खुँटी	48.65
देवघर	47.40
पूर्वी सिंहभुम	23.99
राँची	27.70
धनबाद	28.57
बोकारो	29.40
रामगढ़	29.80
गढ़वा	30.15
सिमडेगा	27.14

Lkzksr % nSfud tkxj.k /kucknk] fnukad 28 uoEcj 2021

धनबाद से प्रकाशित दैनिक जागरण दिनांक 28.11.2021 को प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सबसे गरीब शीर्ष–10 जिलों में संथाल परगना के सभी जिले शामिल है। इस सूची में

पाकुड़ जहां दूसरे नंबर पर तो साहिबगंज चौथे दुमका पांचवें गोड्डा सातवें जामताड़ा आठवें और देवघर दसवें नंबर पर है। राज्य में चतरा जिले में सबसे ज्यादा गरीबी है। वहीं पाकुड़ इस मामले में दूसरे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार चतरा में जहां 63.10 प्रतिशत लोग गरीब है तो पाकुड़ में यह आंकड़ा 61.73 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम में सबसे कम गरीबी है। यहां 23.99 प्रतिशत लोग ही गरीब हैं। इसके बाद रांची में 27.70 प्रतिशत गरीबी है।[11]

2002–2007 में चतरा जिला में बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 16,489 थी। झारखंड में ग्रामीण गरीबी 1993–94 में 66 प्रतिशत थी जो 2004–05 में घटकर 46 प्रतिशत हो गई तथा 2011 में यह घटकर 39.1 प्रतिशत रह गई।

{k= ifjp;

पूर्व में चतरा जिला हजारीबाग जिला का एक उपखण्ड था और इसे जिले के रूप में अधिसूचना संख्या 128 दिनांक 29.05.1991 द्वारा अधिसूचित कर एक पूर्ण जिला के रूप में मान्यता दी गई। चतरा जिला का कुल क्षेत्रफल 3706 वर्ग किलोमीटर है जिसकी आबादी 1042886 है। कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 533935 तथा महिलाओं की संख्या 508951 है। जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का 4.36 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति 32.65 प्रतिशत है। लिंगानुपात 953 तथा जनसंख्या घनत्व 280 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चतरा जिला की साक्षरता दर 60.16 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 69.92 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 49.92 प्रतिशत है।

यहाँ के निवासियों का प्रमुख पेशा कृषि है। 2011 में चतरा जिला में, कुल श्रमिकों के वर्ग में, कृषकों की संख्या 13,799 थी और वे 25.21 प्रतिशत थे, खेतिहर मजदूरों की संख्या 16,766 थी और वे 30.63 प्रतिशत थे, घरेलू उद्योग के श्रमिकों की संख्या 3,015 थी और वे 5.51 प्रतिशत थे और अन्य श्रमिकों की संख्या 21,162 थी और वे 38.66 प्रतिशत थे। कुल श्रमिकों की संख्या 54,742 थी और वे कुल जनसंख्या का 36.25 प्रतिशत थे, और गैर–श्रमिकों की संख्या 96,257 थी और वे कुल जनसंख्या का 63.75 प्रतिशत थे।[12]

Rkkfydk 4 % prjk ftyk tulkf[;dh

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल
कुल जनसख्या	979932	62954	1042886
पुरूष जनसंख्या	500211	3324	503535
महिला जनसंख्या	479721	29230	508951
थ्लंगानुपात	959	867	----
शिशु लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	968	939	----
शिशु जनसंख्या (0–6 वर्ष)	186068	9253	195321
बालक जनसख्या (0–6 वर्ष)	94540	4772	99312
बलिका की जनसख्या (0–6 वर्ष)	91528	4481	96009
साक्षरता	466597	43464	510061
पुरूष साक्षरता	278745	25157	303902
महिला साक्षरता	187852	18307	206159

Lkksr % tux.kuk 2011

lkfgR; leh{kk %

गरीबी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। देश की आजादी के बाद गरीबी उन्तूलन के संबंध में अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, परन्तु वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। प्रस्तावित शोध के लिए वेवसाईट ब्लॉगों, प्रकाशित पुस्तकों, रिपोर्टो आदि का गहन अध्ययन किया जायेगा।

सूर्यनारायण[13] कहते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति ने 1936 में पोषण (प्रति वयस्क श्रमिक 2400 से 2800 कैलोरी), कपड़े (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 30 गज) और आवास (100 वर्ग फुट) के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित करके गरीबी को कम करने के लिए लक्ष्यों को परिभाषित किया।

मिन्हास (1970)[14] ने 1950 के दशक के भारत में गरीबी दर के अपने अनुमान को चक्रीय और प्रत्येक वर्ष की फसल को आधार मानते हुए रिपोर्ट प्रकाशित किया। वे गरीबी के आकलन के लिए कैलोरी उपभोग को आधार मानने से असहतम थे और इन्होंने प्रतिवर्ष व्यय के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण को प्रस्तावित किया। इस आधार पर उन्होंने गणना किया कि वर्ष 1956–57 में भारत में गरीबी दर 65 प्रतिशत थी और इस आधार पर उन्होंने वर्ष 1960 में गरीबी 59 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

दांडेकर एवं रथ (1971)[15] ने 1960 के दशक में गरीबी दर 41 प्रतिशत पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया था। उन्होंने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी प्रतिदिन सेवन

को आधार माना । 1960–61 के घेरलू व्यय के संबंध में एन.एस.एस.ओ. आँकड़ों का उपयोग करते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि भोजन एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ग्रामीण निवासी को प्रति वर्ष 1971 रू. और शहरी निवासी को प्रति वर्ष 3137 रू. की आवश्यकता होती है। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि 1960–61 में 40 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे थे।

सिंघल (2008)[16] ने अपने शोध में बताया कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 1962 में एक कार्य समूह का गठन किा गया था जिसने गरीबी रेखा प्राप्त करने के लिए आवश्यक कैलोरी और भारत के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में उक्त कैलोरी को प्राप्त करने के लिए 1960–61 ई. में 20 रूपया प्रतिमाह खर्च करने पड़ते थे।

योजना आयोग (1979)[17] ने भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न चरों यथा आयु समूहों, लिंग, श्रम स्तर आदि को ध्यान में रखेते हुए उनके बीच कैलोरी की आवश्यकताओं में अंतर के आधार पर निर्धारित किया कि औसत ग्रामीण निवासी को लगभग 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी निवासी को 2100 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्कता होती है और इस आधार पर अनुमान लगाया कि 1973–74 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 49.09 रूपये और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रूपये का उपभोग खर्च उसकी गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए उचित उपाय था।

भारत के लिए गरीबी रेखा की जांच के लिए 1993 में लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक और विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई थी। इसने सिफारिश की कि क्षेत्रीय आर्थिक अंतर इतना बड़ा है कि प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा की गणना की जानी चाहिए। तब से, 1973–74 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए, देश के प्रत्येक राज्य में वस्तुओं की एक मानक सूची तैयार की गई और उनका मूल्य निर्धारित किया गया। वस्तुओं की इस टोकरी की प्रत्येक वर्ष पुनः कीमत तय की जा सकती है और क्षेत्रों के बीच तुलना की जा सकती है। भारत सरकार ने भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए इस पद्धति के एक संशोधित संस्करण का उपयोग शुरू किया।[18]

सक्सेना समिति[19] की रिपोर्ट ने 1972 से 2000 तक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत में गरीबी के आर्थिक विश्लेषण में नाममात्र आय के अलावा कैलोरी सेवन को अलग किया और फिर कहा कि 50% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जांच के लिए गठित सुरेश तेंदुलकर समिति ने नवंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[20] इसने प्रति व्यक्ति प्रति माह या प्रतिदिन उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा की गणना करने की एक नई विधि प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 816 रुपये प्रति माह या 27 रुपये प्रति दिन था। शहरी क्षेत्रों के लिए यह 1000 रुपये प्रति माह या 33 रुपये प्रति दिन था। इस पद्धति का उपयोग करते हुए, 2009–2010 में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 354 मिलियन (जनसंख्या का 29.6%) थी और 2011–2012 में 269 मिलियन (जनसंख्या का 21.9%) थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (2012)[21] ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, गोवा राज्य को 5.09 प्रतिशत की सबसे कम गरीबी वाला राज्य बताया, जबकि राष्ट्रीय औसत 21.92 प्रतिशत था।

विश्वास सौतिक (2018)[22] के अनुसार एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि 2010 से 2015 तक 1.3ः की औसत वृद्धि दर के साथ भारत की जनसंख्या 1.28 बिलियन होगी। 2014 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 9.9 प्रतिशत आबादी कार्यरत थी। 6.9 प्रतिशत आबादी अभी भी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है और 63 प्रतिशत अत्यधिक गरीबी में रहती है

शkks/k vःrjky &

गरीबी और गरीबी रेखा से संबंधित अनेक शोध किए गये हैं जिनमें मुख्यतः आर्थिक पक्षों पर ध्यान दिया गया है, परन्तु सामाजिक पक्षों पर बहुत कम शोध किया गया है। प्रस्तावित शोध का लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे लोगों के आर्थिक के साथ–साथ सामाजिक पक्ष का भी अध्ययन करना है।

शोध उद्देश;

प्रस्तावित शोध के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं :

1. चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वालों की सामाजिक स्थिति (स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा के चरों के आधार पर), अर्थिक स्थिति (आय, व्यय, बचत, अचल सम्पत्ति, रोजगार तथा बैंकिंग सेवओं तक पहुँच के चरों के आधार पर) तथा जनांकीकिय संरचना का अध्ययन करना।

2. चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सामाजिक समूहो (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्गों) के बीच के बहुआयामी सूचकांक (MPI) का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों में गरीबी के आयाम, व्यापकता एवं सघनता का आकलन करना।

4. सरकार द्वारा संचालित एवं प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन और उसमें आ रही समस्याओं का अध्ययन करना।

'kks/k प्रश्u

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों की जनांकीकिय संरचना क्या है ?
2. क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे लोगो के वर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य) के आर्थिक स्तरों में अंतर है ?
3. क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे लोगो के वर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य) के सामाजिक स्तरों में अंतर है ?
4. चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों में गरीबी के आयाम, व्यापकता एवं सघनता एम.पी.आई के आधार पर कितनी है ?
5. चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में कौन–कौन सी योजनाएँ राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाएँ हैं?
6. चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एवं प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख समस्याएँ क्या हैं ?

'kks/k i)fr ,oa midj.k

प्रस्तुत शोध अध्ययन झारखण्ड राज्य के चतरा जिले अन्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड के संदर्भ में किया जाएगा। यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित होगा जो विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक होगा। गरीबी की सघनता एवं व्यापकता को मापने के लिए विगत पाँच वर्षों के आँकड़ों का प्रयोग कर एफ.जी.टी़ इंडेक्स की मदद से विश्लेषण किया जायेगा। एफ.जी.टी. इंडेक्स (फोस्टर ग्रीर थोरबेक सूचकांक) विकास अर्थशास्त्र के अन्तर्गत गरीबी मापन का लोकप्रिय विकल्प है। इसक अन्तर्गत सबसे गरीब व्यक्ति के गरीबी का भारांकन अधिक होता है।

टण्डवा प्रखण्ड की भौगोलिक सीमाएँ पूरब में हजारीबाग जिला, पश्चिम में लातेहार जिला, दक्षिण में राँची जिला तथा उत्तर में चतरा जिला के सिमरिया प्रखण्ड से लगती है। इस प्रकार यह झारखण्ड के तीन प्रखण्डाों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रखण्ड में कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनो की प्रचुरता है। इस प्रखण्ड में संचालित पमुख कोयला खनन परियोजनाएँ – मगध, अम्रपाली, पिपरवार, पर्णडीह आदि है। इसके अतिरिक्त यहाँ एन.टी.पी.सी. का पावर प्लांट भी है। इन सबके बावजूद इस प्रखण्ड में गरीबी चतरा जिला के अन्य प्रखण्डों के समान ही है। इस प्रकार यह प्रखण्ड एक प्रकार से सम्पूर्ण णरखण्ड का प्रतिनिधित्व करती है।

Rkkfydk & 5 % i[k.Mokj prjk ftyk esa xjhch js[kk ds uhps thou&;kiu djus okys ifjokjksa dk vkdM+s ¼,u-vkb-lh- prjk ds vuqlkj½

i[k.M	dqy tula[;k	vUR;ksn; ykHkqdks dh la[;k	ch-ih-,y ykHkqdksa dh la[;k	iqufjf{kr ch-ih-,y ykHkqdksa dh la[;k	dqy ch-ih-,y gkmlgksYm
चतरा नगरपालिका	49985	1623	2187	0	3810
चतरा प्रखण्ड	101014	51636	6964	4362	62962
हंटरगंज	187590	6647	8958	5401	21006
सिमरिया	107871	4592	6186	3085	13863
लवालौंग	50553	1877	2528	2410	6815
पत्थलगडा	31530	1466	1975	1096	4537
टण्डवा	126319	4431	5957	2739	13127
इटखोरी	74929	4341	5847	2711	12899
गिद्धौर	40919	1972	2658	821	5451
प्रतापपुर	120221	5330	7180	3642	16152
कुण्डा	30018	1368	1843	1011	4222
मयुरहण्ड	58925	-----	-----	-----	-----
कान्हाचट्टी	63012	-----	-----	-----	-----
prjk ftyk	**1042886**	**85283**	**52283**	**27278**	**164844**

स्रोत : https://chatra.nic.in/food-and-supply/ (अवलोकन तिथि 04.04.2024)

vkdMk dk lkzr %

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। द्वितीयक आंकड़े चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, विभिन्न बैंको एवं गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त किए जाएंगे।

प्राथमिक आंकड़े की प्राप्ति के लिए एक प्रतिदर्श का चयन किया जायेगा। प्रतिदर्श के चुनाव के लिए चतरा जिले के 12 प्रखण्डों में से टण्डवा प्रखण्ड के 19 पंचायतों में से यादृक्षिक विधि से आठ (8) पंचायतो का चयन कर वहाँ के बी.पी.एल परिवारों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से 200 परिवारों का यादृक्षिक विधि से प्रतिदर्श का चयन किया जायेगा।

SAMPLING FRAME

prjk ftyk

i![k.M

1. चतरा
2. हंटरगंज
3. V.Mok →
4. इटखोरी
5. कान्हाचट्टी
6. कुण्दा
7. मयुरहंड
8. प्रतापपुर
9. गिद्धौर
10. पत्थलगड्डा
11. लावालौंग
12. सिमरिया

lkpk;r

1 पद्मपुर
2 धनगडा
3 राहम
4 मिसरौल
5 नवादा उर्फ तेलियाडीह
6 काबरा
7 पोकला उर्फ काशीडीह
8 कोयद
9 साराधु
10 गाडीलौंग
11 टण्डवा
12 बरगानो
13 डाहु
14 बेंती
15 कल्याणपुर
16 बहेरा
17 किचटो
18 बचरा –। (उत्तर)
19 बचरा – ।। (दक्षिण)

यादृच्छिक विधि द्वारा चुने गये पंचायतो से उत्तरदाताओं की संख्या की गणना

पंचायत – 1	$\frac{200xP_1}{TP}$
पंचायत – 2	$\frac{200xP_2}{TP}$
पंचायत – 3	$\frac{200xP_3}{TP}$
पंचायत – 4	$\frac{200xP_4}{TP}$
पंचायत – 5	$\frac{200xP_5}{TP}$
पंचायत – 6	$\frac{200xP_6}{TP}$
पंचायत – 7	$\frac{200xP_7}{TP}$
पंचायत – 8	$\frac{200xP_8}{TP}$

जहाँ

TP = यादृच्छिक विधि से चयनित 8 पंचायतों की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का योग।

P_1, P_2 .... P_8 –संबंधित पंचायत,ए पंचायत2 ....पंचायत 8 की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या।

इस प्रकार कुल 200 उत्तरदाताओं से पूर्वनिर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा उनके जीवन स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण किया जायेगा और उसका विश्लेषण कर शोध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जायेगा।

'kks/k i:k : lk

प्रस्तावित शोध में तीन मुख्य आयामों को शामिल किया जायेगा :

i) स्वास्थ्य :– इस आयाम में उम्र, शारीरिक वजन एवं ऊँचाई, तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से संबंधी संकेतकों को शामिल किया जायेगा। इस आयाम में यह ज्ञात करने का प्रयास किया जायेगा कि कितने लोग स्वच्छ पीने के पानी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या सुखद स्वास्थ्य सेवा के बिना हैं।

ii) शिक्षा :– इस आयाम में स्कूल जानेवालों की उपस्थिति, पढ़ाई के वर्ष, और शैक्षिक उपलब्धियों जैसे संकेतकों का मूल्यांकन किया जायेगा। इसके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जायेगा कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या कितने बड़े लोग आधारभूत शिक्षा से वंचित हैं।

iii) जीवन स्तर :– इसके अंतर्गत आय, व्यय, बचत, भोजन, स्वच्छता, बिजली, और आवास की गुणवत्ता, सम्पत्ति जैसे अनेक संकेतकों को शामिल किया जायेगा।

çkFkfed vkdMk dk ladyu@laxgu %

चुने गये दोनों प्रतिदर्शों से आँकड़ों का संकलन पुर्व निर्धारित प्रश्नावली के द्वारा उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा। इस प्रश्नावली के द्वारा मुख्यतः रोजगार, आय, उपभोग पर खर्च, बचत, उधार लेन–देन, कर्ज की एवं ऋण के भुगतान की स्थिति, स्वयं के नाम सम्पत्ति, रहन–सहन का स्तर एवं व्यय के अधिकार आदि चरों को मापने के लिए लाभूकों के स्मरण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

vkdMk dk fo″ys"k.k %

संकलित आंकड़ों के द्वारा प्रतिदर्शों का विश्लेषण किया जाएगा। प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण में उपयुक्त सांख्यिकीय विधि जैसे – माध्य, मध्यिका, बहुलक, विचलन, आदि का प्रयोग किया जाएगा।

iLrqr 'kks/k dh iklafxdrk ,oa egRo

झारखण्ड राज्य के आर्थिक उत्थान से संबंधित कई योजनाएं चल रही है किन्तु हम जब गरीबी के विरूद्ध संघर्ष की बात करते हैं तो पाते हैं कि झारखण्ड में गरीबी बहुत अधिक है।

यह अध्ययन चतरा जिले में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जीवन–स्तर, उनके विकास के लिए चलाए जा रहे योजनाओं और उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा जो भविष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह गरीबी को हटाने में मदद करेगा तथा पलायन को रोकेगा साथ ही राज्य के संबंधित विषयक नीति–निर्माण में मददगार होगा।

झारखण्ड के अति पिछड़े जिला में चतरा जिला की गिनती होती है, जहां आज भी लगभग काफी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है तथा गरीबी एवं बेरोजगारी व्याप्त है।

प्रस्तावित शोध से मुख्यतः यह प्रयत्न किया जाएगा कि उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। चतरा जिला में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है तथा शिक्षा का स्तर भी निम्न है। ऐसे में यह अध्ययन सरकार को रोजगार नीति के निर्माण, शिक्षा के विकास और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में मददगार साबित होगी।

यह शोध स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों के लिए नीति निर्धारण एवं वर्तमान स्थिति के अध्यन में सहायक सिद्ध होगा।

प्रस्तावित शोध भविष्य में शोधार्थियों द्वारा किये जाने वाले शोध में मददगार होगा।

lEHkkfor v/;k;

1- परिचय
2- साहित्य समीक्षा एवं शोध विधि
3- चतरा जिला में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन
4- चतरा जिला में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की अर्थिक स्थिति का अध्ययन

5. गरीबी उन्मूलन में उद्योगो की भूमिका एवं उनके प्रभाव

6- गरीबी उन्मूलन के लिए सराकर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा

7- निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ सूची

1. जनगणना 2011–12
2. www.nsso 68th round-discuss.forumias.com/discussion/195
3. जीन ड्रेजे एवं अमर्त्य सेन, 'एन अनसर्टेन ग्लोरी : इंडिया एण्ड इट्स कन्ट्रडिक्संश', प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेसए पृ. 190।
4. भारतीय रिजर्व बैंक (2012), गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत
5. www.nsso 68th round-discuss.forumias.com/discussion/195
6. वही
7. जनगणना, 2011
8. www.worldbank.org/2014/prosperity-for-all-ending-proverty
9. गरीबी के आकलन के लिए पद्धति पर विशेषज्ञ समूह, योजना आयोग ।
10. जीन ड्रेजे एवं अमर्त्य सेन, 'एन अनसर्टेन ग्लोरी : इंडिया एण्ड इट्स कन्ट्रडिक्संश', प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेस।
11. www.nsso 68th round-discuss.forumias.com/discussion/195
12. असमानता और गरीबीए इग्नु द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट
13. चतरा जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना 2011, पृष्ठ 26, जनगणना संचालन निदेशालय, झारखंड ।
14. एम.एच. सूर्यनारायण. गरीबी के लिए पोषण संबंधी मानदंड, मुद्दे और निहितार्थ, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
15. बी.एस. मिन्हास,ग्रामीण गरीबी, भूमि पुनर्वितरण और विकास रणनीति : तथ्य और नीति, भारतीय आर्थिक समीक्षा नई श्रृंखला, वॉल्यूम। 5, नंबर 1 (अप्रैल 1970), पीपी. 97–128
16. दांडेकर एवं रथ (1971) भारत में गरीबी, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक ।
17. अरविंद सिंघल (2008), पिरामिड के निचले भाग में एक बाजार
18. योजना आयोग (1979), गरीबों के अनुपात और संख्या के आकलन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग, योजना आयोग ।
19. योजना आयोग (1993), शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट । .
20. गरीबी पर रंगराजन रिपोर्ट, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार ।
21. गरीबी के आकलन के लिए पद्धति पर विशेषज्ञ समूह, योजना आयोग ।

22. भारतीय रिजर्व बैंक (2012), गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत
23. बिस्वास, सौतिक (15 नवंबर 2017), क्या भारत का मध्यम वर्ग वास्तव में गरीब है? . बीबीसी समाचार
24. दैनिक जागरण
25. www.nsso 68th round-discuss.forumias.com/discussion/195.....
26. www.nfhs-3.org
27. www.rural poverty portal.org-region and country/asia
28. www.rbi.org.in
29. www.chatra.nic.in
30. भारत कैसे गरीब बना हुआ है : भारत के गरीबों को औसत आय तक पहुंचने में 7 पीढ़ियां लगेंगी, - Downtoearth-org-in
31. होमी खरासय लॉरेंस चांडी (2014), अत्यधिक गरीबी समाप्त करने के लक्ष्य के लिए नए मूल्य डेटा का क्या मतलब है? वाशिंगटन डीसी, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन।
32. पूजा मेहरा (2016)। जीडीपी वृद्धि ने गरीबी कम करने में मदद की, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट, द हिंदू
33. ए सेन (1983), गरीबी और अकाल : पात्रता और अभाव पर एक निबंध, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,आईएसबीएन978–0198284635
34. भगवती और पनगढ़िया (2013), विकास क्यों मायने रखता ळे : भारत में आर्थिक विकास ने गरीबी कैसे कम की और अन्य विकासशील देशों के लिए सबक, सार्वजनिक मामले,आईएसबीएन978–1610393737
35. एरेनस्टीन (2011), गरीबी के लिए एक बहुआयामी व्युत्क्रम प्रॉक्सी के रूप में आजीविका संपत्ति, भारतीय इंडो–गैंगेटिक मैदानों का एक जिला–स्तरीय विश्लेषण, जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपेबिलिटीज, 12(2), पीपी 283–302।
36. कृष्णा और शरीफ (2011), राष्ट्रीय रणनीतियों की अप्रासंगिकता? भारत के राज्यों और क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी की गतिशीलता, 1993–2005। विश्व विकास, 39(4), पृ. 533–549
37. पनगढ़िया और मुकीम (2014), भारत में गरीबी का एक व्यापक विश्लेषण। एशियाई विकास समीक्षा, 31(1), पृ. 1–52
38. पॉल, एस. (1989), गरीबी रेखा के निर्माण का एक मॉडल, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 30(1), पीपी. 129–144

39. चेन, एस., जी. दत्त, और एम. रैवेलियन (1994), क्या विकासशील दुनिया में गरीबी बढ़ रही है?, आय और धन की समीक्षा, 40 (4), 359–376।

40. मानस चक्रवर्ती (2014), भारत की गरीबी पर विश्व बैंक ।

41. जागरण दिनांक 28 नवम्बर 2021

42. https://chatra.nic.in/food-and-supply (अवलोकन तिथि 04.04.2024)